



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 579]
[No. 579]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 1984/अग्रहायण 5, 1906
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 1984/AGRAHAYANA 5, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1984

का०आ० 881(अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्न-
लिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित
किया जाता है :—

आदेश

श्री तेज सिंह (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “निर्वाचित
अभ्यर्थी” कहा गया है) जो 1980 में हुए पंजाब विधान
सभा के साधारण निर्वाचन में पंजाब राज्य के 100—बाघा
पुराना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, के
निर्वाचन की उच्चतम न्यायालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त अधि-
नियम” कहा गया है) की धारा 123 के खंड (2) के
अधीन निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा किये गये भ्रष्ट आचरण के
आधार पर 16-1-84 को शून्य घोषित कर दिया गया है;

उच्चतम न्यायालय ने श्री तेज सिंह द्वारा फाइल की गई
पुनर्विलोकन अर्जी को 2-8-1984 को खारिज कर दिया है;

1158 GI/84

राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा
(3) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग की इस बाबत राय
मांगी है कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उक्त अधिनियम की
धारा 8क(1) के अधीन निरहित किया जाना चाहिये
और यदि किया जाये, तो कितनी कालावधि के लिये;

निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपबन्ध देखिए)
दी है कि निर्वाचित अभ्यर्थी को छह वर्ष की ऐसी कालावधि
के लिये निरहित किया जाना चाहिये जिसकी गणना 16
जनवरी, 1984 से, अर्थात् उस तारीख से की जायेगी
जिसको उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन
को शून्य घोषित किया है।

अतः, मैं, जैल सिंह, भारत का राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम
की धारा 8क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूँ, कि निर्वाचित
अभ्यर्थी को 16 जनवरी, 1984 से छह वर्ष की कालावधि
के लिये निरहित घोषित किया जाये।

24 नवम्बर, 1984

(1)

जैल सिंह,
भारत का राष्ट्रपति

उपाख्य

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 1984 का निर्देश
मामला सं० 1 (लौ० प्र० अ०)

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश)
पंजाब विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री तेज सिंह की निरर्हता के बारे में।

राय

यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(1) के साथ पठित उसकी धारा 8क(3) के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त हुआ एक निर्देश है, जिसमें पंजाब विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री तेज सिंह के बारे में निर्वाचन आयोग से इस प्रश्न पर राय मांगी गई है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 123(2) के अधीन भ्रष्ट आचरण करने के लिये उन्हें निरर्हित किया जाये और यदि किया जाये तो कितनी कालावधि के लिये किया जाये।

2. मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में नीचे दिये गये हैं:--

- (1) श्री तेज सिंह 100-बाधा पुराना निर्वाचन क्षेत्र के लिये मई-जून 1980 में हुए साधारण निर्वाचन में अनाली दल के अभ्यर्थी के रूप में पंजाब विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए थे। उनके निर्वाचन को कांग्रेस (इ) के अभ्यर्थी श्री अवतार सिंह ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अधीन श्री तेज सिंह द्वारा किये गये भ्रष्ट आचरणों के आधार पर चुनौती दी थी। जिसमें मुख्यतया यह अधिस्थित किया गया था कि श्री तेज सिंह ने लोकसभा के अन्य विरोधी अभ्यर्थी श्री रूपलाल साथी के नाम से पैम्फलेट और पोस्टर मुद्रित कराये और बंटवाये, जिसमें श्री साथी द्वारा श्री तेज सिंह के पक्ष में अभ्यर्थिता वापस लिये जाने की घोषणा और मतदाताओं से श्री तेज सिंह को मत दिये जाने की अपील करना तात्पर्य था। अर्जीदार ने यह तर्क दिया श्री साथी ने निर्वाचन के अंत तक अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली थी और निर्वाचन के परिणाम को तात्त्विक रूप से प्रभावित करने के लिये श्री तेज सिंह द्वारा श्री साथी के नाम से उपरोक्त पैम्फलेट और पोस्टर जारी करके मतदाताओं के साथ वृहत्पदेशन किया गया है। श्री रूपलाल साथी ने भी उच्च न्यायालय के सनक्ष अर्जीदार के मामले का समर्थन किया। उसके विपरीत श्री तेज सिंह ने अर्जीदार और श्री साथी के अभिकथनों का खण्डन किया और यह बलील दी कि श्री साथी ने उनके पक्ष में 100-बाधा पुराना निर्वाचन क्षेत्र से इस शर्त

पर अपने का निर्वाचन से हटा लिया था और श्री तेज सिंह और उसके कार्यकर्ता समीपस्थ 99-संख्या निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ से वे एक साथ निर्वाचन लड़ रहे थे, उनका (श्री साथी) समर्थन करेंगे।

- (2) उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 22-4-1981 के विनिश्चय में श्री तेज सिंह को बलील का स्वीकार किया और निर्वाचन अर्जी खारिज कर दी।
- (3) तथापि, अपील दिये जाने पर उच्चतम न्यायालय ने मिश्र दृष्टिकोण अपनाया। उच्चतम न्यायालय ने श्री साथी द्वारा क्या अभ्यर्थित अर्जीदार के मामले को स्वीकार किया। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि श्री तेज सिंह ने श्री रूपलाल साथी के नाम से पैम्फलेट और पोस्टर छपवाये और बांटे और उनकी छपाई का खर्च भी श्री तेज सिंह द्वारा किया गया था। श्री तेज सिंह ने उपरोक्त वर्णित पैम्फलेटों और पोस्टरों के मुद्रण प्रभारों का खर्च दिये जाने से इनकार नहीं किया है और उन्होंने इस बारे में जिला निर्वाचन आधिकार को दाखिल की गई निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी के साथ मुद्रण प्रभारों के उक्त भुगतान की बाबत दो बाउचर संलग्न किये थे। तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(2) के अधीन श्री तेज सिंह को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया और तारीख 16-1-1984 को उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया।

3. उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-1-1984 के उपरोक्त विनिश्चय के परिणामस्वरूप, सचिव, पंजाब विधान सभा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के साथ उठाया गया प्रश्न अब यह है कि क्या श्री तेज सिंह को संसद और राज्य विधान मण्डलों के भागामी निर्वाचन लड़ने के लिये निरर्हित किया जाये, और यदि दिया जाये तो कितनी कालावधि के लिये। उक्त प्रश्न का विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति ने मामले को उक्त अधिनियम की धारा 8क(3) के अधीन आयोग को, उसकी राय जानने के लिये, निर्देशित कर दिया है। धारा 8क(1) के परन्तुक के अधीन निरर्हता की अवधि किसी भी दशा में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का तारीख से, (वर्तमान मामले में 16-1-1984 से) छह वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. अपनी राय व्यक्त करने से पूर्व, आयोग ने श्री तेज सिंह को सुनवाई का अवसर देने का विनिश्चय किया। तदनुसार, आयोग ने 2-6-1984 को उनकी सुनवाई की। श्री तेज सिंह स्वयं उपस्थित थे और श्री हरदेव सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता और श्री आर.एस. सोही, अधिवक्ता ने भी उनका प्रतिनिधित्व किया। श्री तेज सिंह की ओर से एक आवेदन

दिया गया जिसमें सुनवाई को इस आधार पर स्थगित करने की प्रार्थना की गई कि उन्होंने तारीख 16-1-1984 के निर्णय और आदेश के पुनर्विलोकन के लिए उच्चतम न्यायालय में पुनर्विलोकन अर्जी फाइल की है और वह उक्त न्यायालय के विधायक है। श्री तेज सिंह की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और सुनवाई को स्थगित कर दिया गया।

5. तारीख 15-9-84 को हुई अगली सुनवाई में, श्री तेज सिंह के स्पष्ट अधिवक्ता, श्री हरदेव सिंह ने सूचित किया कि श्री तेज सिंह को पूर्वका पुनर्विलोकन अर्जी उच्चतम न्यायालय द्वारा 2-8-1984 को खारिज कर दी गई है।

6. पुनर्विलोकन अर्जी के ऐसे खारिज कर दिए जाने के बावजूद, श्री हरदेव सिंह ने मेरे समक्ष उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षों की शुद्धता पर आपत्ति की। उन्हें बताया गया कि आयोग इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता और उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष उस पर बाध्यकारी हैं। फिर भी, उसने यह दलील दी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का ऐसे विवाद्यक से संबंध है जिसे अर्जीदार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की अवस्था पर त्याग दिया था और यह कि उच्चतम न्यायालय ने उस वास्तविक विवाद पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जिस पर पक्षकार उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए गए थे। उसका अनुसार एकमात्र विवाद जो उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए था, विवाद सं. 3 था जिसका संबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के अधीन भ्रष्ट आचरण से था, किन्तु उच्चतम न्यायालय ने उस विवादक पर कोई निष्कर्ष निकालने की बजाए, उक्त अधिनियम की धारा 123(2) के अधीन भ्रष्ट आचरण से संबंधित विवादक सं. 2 के बारे में निष्कर्ष निकाला जिस पर अर्जीदार ने जोर नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त उसने यह भी दलील दी कि जहां तक विवाद सं. 3 का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उस विवादक को श्री तेज सिंह के पक्ष में अवधारित करने हुए यह निर्णय दिया कि श्री तेज सिंह उक्त अधिनियम की धारा 123(4) के अधीन किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं है। इन दलीलों की पुष्टि के लिए उक्त उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के संबंधित पैराग्राफों को निर्दिष्ट किया। इन दलीलों के आधार पर उसने यह तर्क दिया और जुन से यह प्रार्थना की कि मैं यह निष्कर्ष निकालूँ और विश्वास करूँ कि न तो उच्च न्यायालय ने और न उच्चतम न्यायालय ने ही श्री तेज सिंह के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण का कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है।

7. 15-9-1984 को हुई सुनवाई में श्री हरदेव सिंह द्वारा दी गई मौखिक दलीलें उसी दिन उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित तर्कों में भी दोहराई गईं।

8. मैंने श्री तेज सिंह के विद्वान काउंसल, श्री हरदेव सिंह की उपर्युक्त दलीलों और विवादों पर विचार किया।

किसी गुणागुण के रहित होने के कारण उन्हें नामंजूर करने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। जैसी कि श्री हरदेव सिंह ने बलीज दी है, यदि श्री तेज सिंह किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया जाता है तो क्या वह, या उस मामले में कोई भी व्यक्ति स्पष्टीकरण दे सकता है कि श्री तेज सिंह का निर्वाचन क्यों शून्य घोषित किया गया है? इनके अतिरिक्त तारीख 16-1-1984 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 4, 7 और 8 में उसके निम्नलिखित स्पष्ट और असंदिग्ध निष्कर्षों के बावजूद कोई भी व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि तेज सिंह के विरुद्ध कोई भ्रष्ट आचरण नहीं पाया गया है:—

“पक्षकारों द्वारा दिए गए साक्ष्य—मौखिक और दस्तावेजी दोनों—के परिणाम के पश्चात् हमारी स्पष्ट राय है कि तेज सिंह द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरणों के आरोप स्पष्ट रूप से साबित हो गए हैं.....

इन परिस्थितियों में, हमारा समाधान हो गया है कि अपीलार्थी ने युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है कि तेज सिंह ने भ्रष्ट आचरण किया है, विशेष रूप से तब जब तेज सिंह ने जैसा कि ऊपर उपदिष्ट है, स्पष्टतः यह स्वीकार किया है कि उसने पोस्टर मुद्रित कराए हैं। अपीलार्थी द्वारा दिए गए अन्य आधारों के अलावा, जिन पर हमारे समक्ष वास्तव में जोर नहीं दिया गया है अपीलार्थी इस आधार पर ही सफल होने का हकदार है कि प्रथम प्रत्यर्थी (तेज सिंह) ने उक्त अधिनियम की धारा 123(2) के अधीन यथा अनुव्यात भ्रष्ट आचरण (जिसका निर्देश ऊपर किया गया है) किया है और वह आचरण पूर्णतः साबित हो गया है।”

इनके अतिरिक्त श्री तेज सिंह ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपनी पुनर्विलोकन अर्जी में उस समय परोक्षतः स्वयं यह स्वीकार किया है कि उच्चतम न्यायालय ने उसे भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया है जब उसे अपनी पुनर्विलोकन अर्जी के पैरा 10 में दलील दी है कि उसकी “एक मात्र जिन्ता अधिनियम की धारा 123(2) के अधीन उसके भ्रष्ट आचरण के दोषी होने के फलस्वरूप है।”

9. इसी प्रकार उसकी अन्य दलीलें भी सारहीन हैं उच्चतम न्यायालय का निष्कर्ष एक ऐसे विवादक से संबंधित है जो उच्च न्यायालय के समक्ष अर्जीदार ने त्याग दिया था। यह स्वीकृत है कि पक्षकार विवादक सं. 3 के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए गए थे। निस्संदेह उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष उसी विवादक से संबंधित है। उस विवादक को उच्च न्यायालय ने बहुत सतर्कता से रचना की थी और उसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के ऐसे किसी विनिर्दिष्ट उपबंध का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें खंडन के रूप में, भ्रष्ट आचरण के आरोप को, जो विवादक सं. 2 है, उस अधिनियम की धारा से

विनिर्दिष्ट रूप से संबंधित किया गया है। यदि उच्चतम न्यायालय ने, अपने विवेकानुसार, अभिनिर्धारित किया है कि विवाहक सं. 3 के अधीन साबित होने वाले भ्रष्ट आचरण के आरोप को उक्त अधिनियम की धारा 123(2) के दायिक उपबंध लागू होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति की उच्चतम न्यायालय के उन निष्कर्षों पर आपत्ति करने की स्वतन्त्रता नहीं है, विधिप्रणाली निर्वाचन आयोग के समक्ष वर्तमान कार्यवाहियों में, क्योंकि आयोग उन निष्कर्षों से शाश्वत है। इसके अतिरिक्त, यदि उपर्युक्त दलील में कोई सार है तो भी श्री तेज सिंह की पुनर्विनोदक की उम्र अर्जी के, जिसमें इसी प्रश्न का उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद किया गया है, नाबंजूर कर दिए जाने को ध्यान में रखते हुए, उसका प्रभाव समाप्त हो गया है।

10. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निःसंदेह यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने श्री तेज सिंह को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया है। तब प्रश्न यह उठता है कि क्या उक्त भ्रष्ट आचरण करने के लिए उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा (8क)(1) के अधीन निरहित किया जाना चाहिए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए। श्री तेज सिंह की ओर से विद्वान काउंसिल अपराध से बचाने वाली या उसे कम गंभीर करने वाली ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बता सके है जिससे अपराध की गंभीरता कम होती हो और श्री तेज सिंह के मामले में उक्त धारा (8क)(1) के उपबंध पूर्णतः लागू न होने को न्यायचित ठहराती हो। किसी निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण का किया जाना एक गंभीर बान है और उस पर पूर्ण गंभीरता और चिन्ता से विचार किया जाना बांछनीय है। किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने विरोधी अभ्यर्थी के नाम से ऐसा झूठा पोस्टर प्रकाशित करना, जिसका तात्पर्य यह है कि ऐसे विरोधी अभ्यर्थी ने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है और उसके पक्षधर मतदाता अपना मत पूर्वकथित अभ्यर्थी (तेज सिंह) के पक्ष में दे, से यह अपील की गई हो, एक निन्दनीय कार्य है और इसको कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। प्रजातन्त्रीय निर्वाचन न केवल स्वतन्त्र और निष्पक्ष हाना चाहिए बल्कि वह स्वतन्त्र और निष्पक्ष लगना भी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को, जो जानबूझकर निर्वाचकों को भ्रमित करता है और विरोधी अभ्यर्थी को क्षति पहुंचाकर कुछ अतिरिक्त मत प्राप्त करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करता है, वेदाग नहीं छोड़ा जाना चाहिए और उसके भ्रष्ट आचरण के लिए उसे विधि के अधीन पूर्णतः दण्ड दिया जाना चाहिए। अतः मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि श्री तेज सिंह को उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से पूरे छह वर्ष की अवधि के लिए, क्यों नहीं निरहित किया जाना चाहिए, जैसा कि विधि में अभिकल्पित है।

11. उपर्युक्त कारणों से मेरी राय है और तदनुसार मैं यह अभिनिर्धारित करता हूँ कि श्री तेज सिंह को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(1) के उपबंधों के अधीन उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से,

अर्थात् 16-1-1984 से, छह वर्ष के लिए निरहित किया जाना चाहिए। तदनुसार मैंने उपर्युक्त आशय की अपेक्षा राय उक्त अधिनियम की धारा 8क(3) के अनुसार राष्ट्रपति को दे दी है।

नई दिल्ली,

9 अक्टूबर, 1984

(आर.के. तिवेदी),

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[फा.सं. 7(21)/84-वि. II]

क. सुब्रामणियन,

संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1984

S.O. 881(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas the election of Shri Tej Singh (hereinafter referred to as the "returned candidate"), a returned candidate from 100-Baghapurana assembly constituency in the State of Punjab at the general election to the legislative assembly of Punjab held in 1980 was declared void by the Supreme Court on 16-1-1984 on the ground of commission by the returned candidate of the corrupt practices under clause (2) of section 123 of the Representation of People Act, 1951 (hereinafter referred to as the "said Act") ;

And, whereas, the Supreme Court on 2-8-1984 dismissed the review petition filed by Shri Tej Singh ;

And, whereas, the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act on the question whether the returned candidate should be disqualified under section 8A(1) of the said Act, and if so, for what period ;

And, whereas, the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the returned candidate should be disqualified for a period of six years to be reckoned from the 16th January, 1984, i.e. the date of the judgement of the Supreme Court declaring the election of the returned candidate void ;

Now, therefore, I, Zail Singh, President of India, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (3) of section 8A of the said Act do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of six years from the 16th January, 1984.

ZAIL SINGH,
President of India

The 24 November, 1984.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA
BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF
INDIA

Reference Case No. 1 (RPA) of 1984

[Reference from the President of India under Section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951]

In re : Disqualification of Shri Tej Singh, former member of Punjab Legislative Assembly.

OPINION

This is a reference from the President under section 8A(3) read with section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Tej Singh, former member of Punjab Legislative Assembly may be disqualified and, if so, for what period for committing corrupt practice under section 123(2) of the said Act.

2. The relevant facts of the case may be briefly stated as under :—

- (i) Shri Tej Singh was elected to the Punjab Legislative Assembly from 100-Baghapurana assembly constituency as an Akali Dal candidate at the general election held in May-June, 1980. His election was challenged by Shri Avtar Singh, rival Congress(I) candidate, on the ground that Shri Tej Singh had committed corrupt practices under section 123 of the Representation of the People Act, 1951. It was mainly alleged that Shri Tej Singh got printed and distributed pamphlets and posters in the name of Shri Ruplal Sathi another rival candidate belonging to Lok Dal in which Shri Sathi purported to announce withdrawal of his candidature in favour of Shri Tej Singh and appealed to voters to vote for Shri Tej Singh. The petitioner contended that Shri Sathi had not withdrawn from the contest till the end and that the misrepresentation made to the voters by means of above pamphlets and posters issued by Shri Tej Singh in the name of Shri Sathi materially affected the result of election. Shri Ruplal Sathi also supported the case of the petitioner before the High Court. Shri Tej Singh on the other hand, refuted the allegations of the petitioner and of Shri Sathi and contended that Shri Sathi had withdrawn from contest in his favour in 100-Baghapurana constituency in consideration of his (Shri Tej Singh's) and his workers' support for him (Shri Sathi) in the adjoining 99-Moga constituency from where also Shri Sathi was contesting election simultaneously.
- (ii) The High Court by its decision dated 22-4-1981 accepted the version of Shri Tej Singh and dismissed the election petition.

- (iii) On appeal, the Supreme Court, however, held differently. The Supreme Court accepted the petitioner's case as supported by Shri Sathi. The Supreme Court observed that the pamphlets and posters were not printed and distributed by Shri Tej Singh in the name of Shri Ruplal Sathi and that the payment for their printing was also made by Shri Tej Singh. Shri Tej Singh had not denied the payment of printing charges of the above mentioned pamphlets and posters and had annexed the two vouchers in respect of the said payment of printing charges, to the return of his election expenses lodged with the District Election Officer. The Supreme Court accordingly found Shri Tej Singh guilty of corrupt practice under section 123(2) of the Representation of the People Act, 1951 and declared his election void on 16-1-1984.

3. As a sequel to the Supreme Court's above decision, dated 16-1-1984, the question has now been raised before the President by the Secretary, Punjab Legislative Assembly in terms of section 8A(1) of the Representation of the People Act 1951, whether Shri Tej Singh may be disqualified for contesting future elections to Parliament and State Legislatures and, if so, for what period. Before deciding that question the President has referred the matter to the Commission for its opinion under section 8A(3) of the said Act. Under the proviso to section 8A(1), the period of disqualification shall in no case exceed six years from the date of the decision of the Supreme Court, i.e. 16-1-1984, in the present case.

4. Before formulating its opinion, the Commission decided to afford to Shri Tej Singh an opportunity of being heard. Accordingly, a hearing was held by the Commission on 2-6-1984. Shri Tej Singh was present in person and was also represented by Shri Hardev Singh, senior Advocate and Shri R. S. Sodhi, Advocate. An application was moved on behalf of Shri Tej Singh praying for adjournment of the hearing on the ground that he had filed a review petition before the Supreme Court seeking review of its judgment and order dated 16-1-1984, which was stated to be pending consideration of the Court then. The prayer of Shri Tej Singh was granted and the hearing was adjourned.

5. At the next hearing held on 15-9-1984, Shri Hardev Singh, Senior Counsel for Shri Tej Singh, informed that the aforesaid review petition of Shri Tej Singh had been dismissed by the Supreme Court on 2-8-1984.

6. Despite such dismissal of the review petition, Shri Hardev Singh sought to question before me the correctness of the findings of the Supreme Court. He was told that the Commission could not go into that question and was bound by the findings of the Supreme Court. Nevertheless, he submitted that the finding given by the Supreme Court related to an issue which was given up by the petitioner at the trial stage before the Punjab and Haryana High Court and that the Supreme Court did not give any finding on the

actual issue on which the parties went to trial before the High Court. According to him the only issue on which the parties went to trial before the High Court was issue No. 3 which related to a corrupt practice under section 123(4) of the Representation of the People Act, but the Supreme Court had not given any finding on that issue and had instead given its findings in regard to issue No. 2 relating to a corrupt practice under Section 123(2) of the said Act, which issue was not pressed by the petitioner. He further submitted that in so far as issue No. 3 was concerned, the High Court found that issue in favour of Shri Tej Singh holding him not guilty of any corrupt practice under section 123(4) of the said Act. To substantiate these submissions, he referred to various paragraphs of the judgments of High Court and the Supreme Court. On the basis of these submissions, he contended, and urged me to infer and believe, that neither the High Court nor the Supreme Court had given any adverse finding of corrupt practice against Shri Tej Singh.

7. The oral submissions made by Shri Hardev Singh at the hearing held on 15-9-1984 were subsequently reiterated in the written arguments submitted by him on the same day.

8. I have considered the above submissions and contentions of Shri Hardev Singh, the learned counsel of Shri Tej Singh. It hardly needs any argument to reject them as being devoid of any merit. If Shri Tej Singh has not been found guilty of any corrupt practice, as contended by Shri Hardev Singh, then can he, or anyone for that matter, explain why Shri Tej Singh's election has been declared void? Again, how can anyone say that there is no finding of corrupt practice against Shri Tej Singh in the face of the following categorical and unambiguous findings of the Supreme Court in paras 4, 7 and 8 of its judgment dated 16-1-1984 :—

"On a perusal of the evidence—both oral and documentary adduced by the parties we are clearly of the opinion that the allegations of corrupt practices indulged in by Tej Singh have been clearly proved....."

In these circumstances, we are satisfied that the Appellant has proved beyond reasonable doubt that Tej Singh had indulged in corrupt practices particularly when the printing of the posters by Tej Singh has been clearly admitted by him as indicated above.....Leaving aside other grounds taken by the appellant which were in fact not pressed before us, the appellant is entitled to succeed on the ground of corrupt practices (referred to above) as contemplated by section 123(2) of the Act having been adopted by the first respondent (Tej Singh) which have been fully proved."

Further, Shri Tej Singh has himself virtually admitted in his review petition filed before the Supreme Court that he has been found guilty of a corrupt practice by the Supreme Court when he submitted in para 10 of his review petition that his "sole concern is the consequence flowing from his having been held to be guilty of corrupt practices under section 123(2) of the Act."

9. Likewise, there is no merit in his other contention that the finding of the Supreme Court relates to an issue which was given up by the petitioner before the High Court. Admittedly, the parties went to trial before the High Court on issue No. 3; undoubtedly, the findings of the Supreme Court relate to that very issue. That issue has been very guardedly framed by the High Court and there is no mention of any specific provision of the Representation of the People Act, 1951 therein, whereas, in contradistinction, the charge of corrupt practice covered by issue No. 2 has been specifically made relatable to section 123(2) of that Act. If the Supreme Court has, in its wisdom held that the charge of corrupt practices proved under issue No. 3 attracts the penal provisions of section 123(2) of the said Act, it is not open to anyone to assail those findings of the Supreme Court, particularly in the present proceedings before the Election Commission as the Commission is bound by those findings. In the next place, even if there was any merit in the above contention the same has lost its force in view of the rejection of the review petition of Shri Tej Singh wherein this very question has been agitated before the Supreme Court.

10. In view of the foregoing, it is clear beyond any pale of doubt that Shri Tej Singh has been found guilty of corrupt practice by the Supreme Court. The question then arises whether he should be disqualified for having committed that corrupt practice and if so, for what period under the provisions of section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951. The learned counsel for Shri Tej Singh has not been able to show any extenuating or mitigating circumstance which might have diluted the gravity of the offence and might have justified the provisions of the said section 8A(1) being not applied with full rigour in the case of Shri Tej Singh. The Commission of a corrupt practice at an election is a very grave matter and deserves to be viewed with all seriousness and concern. The publication of a false poster by a candidate in the name of a rival candidate purporting to be an appeal in the name of the latter to the electorate that the latter had withdrawn from the contest and that his supporters should vote for the former is a deplorable act and should be condemned in the strongest terms. A democratic election should not only be free and fair but should also seem to be free and fair. A candidate who deliberately misleads the electorate and sullies the election proceedings to procure some extra votes at the cost of the rival candidate cannot be allowed to go scot-free and his act of corrupt practice must be visited with full penal conse-

ences under the law. Therefore, I do not see any reason why Shri Tej Singh should not be disqualified for the full term of six years from the date of the Supreme Court's order, as envisaged under the law.

11. For the foregoing reasons, I am of the opinion and accordingly hold that Shri Tej Singh should be disqualified for six years from the date of the Supreme Court's order, i.e. 16-1-1984, under the provisions of section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951. I accordingly tender my opinion to the

above effect to the President in terms of section 8A (3) of the said Act

R. K. TRIVEDI
Chief Election Commissioner of India

[No. F. 7(21)/84-Leg.II]
K. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.

New Delhi,
October 9, 1984

